मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1851
9 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

स्मार्ट सिटी मिशनों के अंतर्गत चयनित शहर

1851. श्री किशन कपूर:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश के चयनित शहरों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त शहरों के विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच धनराशि के आवंटन के मानदंड क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त शहरों के विकास का आकलन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की शुरूआत की थी। जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 दौर के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है।

(ख): स्मार्ट सिटीज मिशन के विवरण और दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, अर्थात प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रूपए प्रति शहर। राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा बराबरी आधार पर एक समान राशि का योगदान किया जाना है।

(ग): शहरी स्तर पर एससीएम का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया जाता है। एसपीवी अपनी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन का समन्वयन राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, एससीएम के कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। एसपीवी के बोर्ड में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरों के प्रदर्शन का

आकलन करने और उन्हें सुधारने के लिए विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं आदि के माध्यम से राज्यों/स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है। स्मार्ट शहर नियमित रूप से ऑनलाइन भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) के माध्यम से निधियों की उपयोगिता सहित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हैं।

******